RNI : UAHIN/25/A3210

आवाम इंडिया

हिन्दी साप्ताहिक

वर्षः 01 अंकः 07 देहरादून, शुक्रवार 22 मई 2026 मूल्य 2 रुपये पृष्ठः 8 www.aawamindia.com

हमारी आत्मा, हमारी पहचान

उत्तराखण्डियत की ओर

मौं. वसी जैदी

भारत के उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में बसा उत्तराखण्ड केवल एक राज्य नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा, प्रकृति और लोकजीवन का अद्भुत संगम है। ये हमारी विरासत है उस हजारों साल की सभ्यता और संस्कृति की जिसने हमें जीना सिखाया है। ये नजरिया है उस अहसास का जो हमारी पहचान है और मां गंगा की अविरल धारा की तरह देश और दुनिया को पोषित कर रही है। उत्तराखण्ड की मिट्टी के कण-कण में असीम आस्था और विश्वास की सुगंध है। लोकगीतों की मिठास है, संघर्ष की कहानी है और सरलता, वीरता और आत्मीयता की गहरी छाप है। इन्हीं विशेषताओं को समेटे हुए "उत्तराखण्डियत" एक ऐसी भावना है, जो केवल भौगोलिक पहचान नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का प्रतीक है।

उत्तराखण्डियत का अर्थ उस विचारधारा का नाम है, जिसमें प्रकृति के प्रति सम्मान, लोकसंस्कृति के प्रति गर्व, सामूहिकता की भावना, शौर्यता और वीरता का प्रतीक और संघर्ष के बीच मुस्कुराकर जीने की कला शामिल है। यह भावना पहाड़ के सुदूर दुर्गम क्षेत्र से लेकर मैदान तक वीरता और संघर्ष की कहानी लिखती है। नवम्बर 2000 में जब अपना प्रदेश मिला तो हजारों सपनों के बीच हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी थी कि हम प्रदेश का ऐसे निर्माण करे कि अन्य राज्यों के लिए मिसाल हो। जिस संघर्ष के साथ लड़कर हमें राज्यों मिला था वो संघर्ष छोटा नहीं था। वो संघर्ष पहाड़ में पहाड़ की भावना को जीवंत रखने का आंदोलन था। उस संघर्ष से ही तो उत्तराखण्डियत का जन्म हुआ था। अब करीब 26 सालों के इस सफर मे हम उत्तराखण्डियत के मार्ग पर कितना आगे बढ़े और कितना आगे बढ़ना बाकी है, इस पर गहन विचार करना आवश्यक है।

आज आधुनिकता के दौर में उत्तराखण्ड की नई पीढ़ी अपनी जड़ों से दूर होती दिखाई दे रही है। मोबाइल और सोशल मीडिया के प्रभाव के बीच लोकभाषाएँ और लोकसंस्कृति धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही हैं। गढ़वाली और कुमाऊँनी और जौनसारी जैसी भाषाएँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, लेकिन हमारी नई पीढ़ी के जीवन में उस तरह शामिल नहीं है जैसे होनी चाहिए थी। हमारे लोकनृत्य जैसे झोड़ा, चांचरी और छोलिया केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का माध्यम रहे हैं। लोकगायक और लोककलाकार अपनी आवाज में पहाड़ की पीड़ा, प्रेम और संघर्ष को जीवंत कर देते हैं। "बेडू पाको बारामासा" जैसे गीत आज भी उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान माने जाते हैं। उत्तराखण्डियत इसी सांस्कृतिक चेतना को ही जीवित रखने की प्रेरणा देती है। कितना अच्छा हो यदि हमारी इस सांस्कृतिक पहचान और भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। हमारी भाषा सिर्फ बोली-भाषा तक सीमित ना हो। हमारी भाषा की एक लिपि हो और एक दर्जा प्राप्त हो।

दूसरा पहाड़ को जीवंत बनाये रखने की आवश्यकता महसूस होती रही है। उत्तराखण्ड के निर्माण को करीब 26 साल हो गये हैं लेकिन पलायन आज भी बड़ी चिंता है। पहाड़ खाली हुए हैं और तेजी से खाली हुए है। पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाये देने के लिए सरकार ने अपने-अपने स्तर पर प्रयास जरूर किये हैं लेकिन अभी और तेजी से इस कमी को भरा जाना आवश्यक है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार पर ठोस और कारगर नीति बनाकर कार्य करने होंगे। आधुनिक कृषि को पहाड़ में विकसित किया जाये। छोटे-छोटे उद्योग स्थापित हो, डॉक्टरों और शिक्षकों की कमी ना हो। सरकारी शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाये, प्राकृतिक आपदा और चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयारी रहे तो उत्तराखण्डियत की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

तीसरा प्राकृतिक संरक्षण की भी दिशा और दशा तय होनी चाहिए। हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। हमीं ने चिपको आंदोलन किया था। हमारे ही बुजुर्ग थे जो पेड़ों से लिपटकर खड़े हो गये थे। प्राकृतिक संरक्षण का जो संदेश हमनें दिया उसे पूरी दुनिया ने समझा लेकिन आज हमीं समझने में पीछे रह गये। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में तालमेल ही नहीं बना पाये। एक मजबूत संतुलन ना पहाड़ की प्राकृतिक आपदाओं को किसी हद तक कम कर सकता है बल्कि आर्थिक आय के अवसर भी पैदा कर सकता है। हाल ही के दिनों में धराली में जो हुआ और उससे पहले रैणी में जो हुआ वो सिर्फ प्राकृतिक आपदायें नहीं थी। वो मानव द्वारा निर्मित प्राकृतिक असंतुलन का जीता-जागता उदाहरण था। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी बेहतर तरीके से पहाड़ के काम आ सकती है। बहुत संभावनायें हैं। बस उन संभावनाओं पर सुनियोजित तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है।

सबसे अहम इन सभी मुद्दों को राजनीतिक कार्यशैली जोड़ती है। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि एक लम्बे समय तक हमारी राजनीति अस्थिर रही। जब प्रदेश का आंदोलन चरम पर था और हमारी मांग एक अलग राज्य की होती थी तो अधिकतर लोग केंद्र

शेष पृष्ठ दो पर

राज्यों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को और अधिक मजबूत किया जाना आवश्यक

संवाददाता

देहरादून। बस्तर, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद् की 26वीं बैठक में उत्तराखण्ड

के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहभागिता की। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, आधारभूत संरचनाओं के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों को प्रमुखता से रखते हुए कहा कि राज्यों के बीच बेहतर संवाद, सहयोग और समन्वय से ही देश के समग्र एवं संतुलित विकास को नई गति प्रदान की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में सहकारी एवं समन्वित संघीय व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान उत्तराखण्ड में वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां नंदा राजजात यात्रा और दिव्य एवं भव्य कुंभ मेले की तैयारियों से संबंधित विषयों को भी प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि ये दोनों आयोजन केवल उत्तराखण्ड ही नहीं, बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन हैं। इन आयोजनों में देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुविधा, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा विभिन्न व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए केंद्र एवं राज्यों के समन्वित सहयोग की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक विरासत और आध्यात्मिक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्यों के सहयोग से मां नंदा राजजात यात्रा और कुंभ मेले का आयोजन अत्यंत सुव्यवस्थित, सुरक्षित और ऐतिहासिक रूप से सफल होगा।बैठक में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्यों के मध्य समन्वय बढ़ाने, साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, आपदा प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा तकनीकी संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्यों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं संयुक्त प्रयासों को और अधिक मजबूत किया जाना आवश्यक है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार जनकल्याण, सुशासन, आधारभूत विकास, पर्यटन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा युवाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत'के संकल्प को साकार करने हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित विभिन्न राज्यों के मंत्रीगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे।

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने ग्राम बंदरजूड का दौरा किया

संवाददाता

रूडकी। उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कघसमी ने आज

जनपद हरिद्वार के ग्राम बंदरजूड का दौरा किया, जहां पर हलाला मामले में पहला मुकदमा जहाँ समान नागरिक संहिता के अंतर्गत दर्ज हलाला के प्रथम प्रकरण से संबंधित पीड़िता के परिवारजनों से भेंट कर उनका हालचाल जाना तथा उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति आश्वस्त किया।

इस अवसर पर मुफ्ती शमून कघसमी ने कहा कि उत्तराखण्ड में लागू समान नागरिक संहिता महिलाओं की गरिमा, समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने साहसिक नेतृत्व का परिचय देते हुए समाज में व्याप्त कुप्रथाओं के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाया उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी का नेतृत्व युवा, ऊर्जावान, पारदर्शी और जनकल्याणकारी नेतृत्व का प्रतीक है तथा उनके नेतृत्व में उत्तराखण्ड विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय के नए आयाम स्थापित कर रहा है।मुफ्ती शमून कघसमी ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लागू की गई समान नागरिक संहिता संविधान की भावना के अनुरूप है और इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार एवं समान न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि समाज को धर्म के नाम पर चल रही कुप्रथाओं और शोषणकारी प्रथाओं के विरुद्ध एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। कघसमी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने केवल एक कानून लागू नहीं किया, बल्कि समाज में व्याप्त अन्याय, भेदभाव और कुप्रथाओं के विरुद्ध एक व्यापक सामाजिक जागरण का कार्य किया है।

दौरे के दौरान स्थानीय ग्रामीणों एवं सामाजिक प्रतिनिधियों ने भी माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया तथा क्षेत्रीय सामाजिक एवं शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा की। श्री मुफ्ती शमून कघसमी ने ग्रामीणों से सामाजिक सद्भाव, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सामाजिक सुधार, महिला सम्मान और संवैधानिक मूल्यों की दिशा में एक नए युग की शुरुआत कर रहा है तथा राज्य सरकार के प्रयास देश के लिए प्रेरणास्रोत बन सकते हैं।बाद में राज्यमंत्री शमून कासमी ने अंतरराष्ट्रीय शायर अफजल मंगलोरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किए जाने पर उनके रुड़की आवास पहुँच कर बधाई दी और उनका अभिनन्दन किया।इस अवसर पर उत्तराखंड नागरिक सम्मान समिति के सचिव सलमान फरीदी, इमरान देशभक्त, सयैद नफिसुल हसन ,बिटन त्यागी आदि मौजूद रहे।

आईटीबीपी 8 वीं वाहिनी गौचर में हुई वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत ताजा फल एवं सब्जियों की आपूर्ति

गौचर / चमोली। वाईब्रेंट बिलेज कार्यक्रम के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 वीं वाहिनी आईटीबीपी गौचर में ताजा फल एवं सब्जियों की पहली आपूर्ति हो गई है।सेनानी 8 वीं

वाहिनी आईटीबीपी गौचर मनोहर सिंह रावत ने बताया कि वाइब्रेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत 01 अप्रैल 2026 को मनु महाराज, महानिरीक्षक उत्तरी फ्रंटियर मुख्यालय (देहरादून) के निर्देशन और उत्तराखंड औधौगिक विकास परिषद के मध्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में हुऐ समझोता ज्ञापन (एम. ओ. यू.) के तहत 18 मई 2026 को 8 वीं वाहिनी गौचर में ताजा फल एवं सब्जियों की पहली आपूर्ति कराई गई है।मनोहर सिंह रावत सेनानी 8 वीं वाहिनी आईटीबीपी गौचर ने इस सराहनीय पहल की प्रशंसा करते हुऐ कहा कि इस प्रकार के प्रयासों से सीमांत एवं ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय लोगो को स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगें, साथ ही उनकी आय के साधनों में निरन्तर वृद्धि होने की प्रवल संम्भावना है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को सीधे बाजार एवं आईटीबीपी जैसे बड़े संस्थानों से जोड़ने से किसानों एवं उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त होगा। जिससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने तथा स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान करने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम है।

हमारी आत्मा, हमारी पहचान.....

पृष्ठ 1 का शेष

शासित राज्य चाहते थे। उसका लाभ ये होता कि हमारी आर्थिकी बेहतर हो जाती। केंद्रिय योजनाएं और पैसा हमारे संसाधानों को बेहतर कर सकता था। हालांकि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दयालुता दिखाकर अपने पूर्ण राज्य का दर्जा दिया लेकिन राजनीतिक का स्तर तो हमें ही सुधारना था। हम बहुत कम समय में एक के बाद एक मुख्यमंत्री देते रहे। सब प्रतिभाशाली लोग थे लेकिन पलटकर वापिस नहीं आ पाये। अब थोड़ी सी स्थिरता दिखायी देती है। पुष्कर सिंह धामी लगभग 5 साल से प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखण्ड से विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री बनने के बाद 18 बार वो प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। प्रदेश की हर परिस्थिति से वाकिफ हैं और कई मंच पर अपने संबोधन में ये कह चुके है कि ये दशक उत्तराखण्ड का दशक है। कुल मिलाकर ये प्रदेश के विकास और भविष्य निर्माण का सुनहरा दौर है।

उत्तराखण्डियत में वीर भूमि उत्तराखण्ड की चर्चा करना भी आवश्यक है। यह एक मात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। उत्तराखण्ड कल भी वीरता के क्षेत्र में आगे था, आज भी वीरता के क्षेत्र में आगे हैं। आज भी घर-घर से सैनिक देश पर कुरबान होने के लिए निकलते हैं। देश सेवा का जो जज्बा यहां की मिट्टी में हैं वो शायद ही कहीं ओर हो।

अब उत्तराखण्डियत केवल अतीत की स्मृतियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसे वर्तमान और भविष्य की दिशा बनाना होगा। उत्तराखण्ड का हर नागरिक अपनी संस्कृति और पहचान पर गर्व करे। उत्तराखण्डियत का अर्थ केवल पहाड़ी पहनावा या बोली नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत, प्रकृति प्रेम और सामाजिक एकता की भावना है। यही वह विचारधारा है, जो उत्तराखण्ड को देश के अन्य राज्यों से अलग पहचान देता है। यही उत्तराखण्डियत है, और यही उत्तराखण्ड की सबसे बड़ी ताकत भी है।

सीएम बोले: उत्तराखण्ड आदि अनादि काल से देवों की भूमि

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नानकमत्ता में आयोजित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती समारोह का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया तथा बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नानकमत्ता साहिब की पावन धरती, जहां गुरुओं का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, वहां महाराणा प्रताप जैसे महान राष्ट्रनायक का स्मरण करना गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ के शासक नहीं थे, बल्कि भारत की आन, बान और स्वाभिमान के अमर प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग, संघर्ष, साहस और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणादायी गाथा है, जो आज भी हर भारतीय को ऊर्जा और गौरव से भर देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह संदेश देता है कि राष्ट्र, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने थारू समाज की परंपराओं, लोकगीतों, लोकनृत्यों और प्रकृति से जुड़ी जीवनशैली को उत्तराखंड की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर बताया। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, स्वाभिमान और समग्र विकास के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, वन धन योजना, जनजातीय विकास मिशन और अन्य योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी जनजातीय समाज के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अटल आवास योजना के अंतर्गत आय सीमा को व्यावहारिक बनाया गया है तथा आवास निर्माण सहायता बढ़ाई गई है। उधम सिंह नगर में इस योजना के तहत लगभग 3 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से भी बड़ी संख्या में जनजातीय परिवार लाभान्वित हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से आश्रम पद्धति विद्यालयों, छात्रावासों और आईटीआई संस्थानों के विकास के लिए करोड़ों रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। खटीमा में बालिका छात्रावास के लिए 4 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जबकि बाजपुर में 16 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। गदरपुर में 100 बेड का छात्रावास भी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आजीविका मिशन और वन धन केंद्रों के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं को 1 करोड़ रुपये से अधिक की चक्रीय निधि और 8 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश सहायता प्रदान की गई है। इसके साथ ही जनजातीय शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड भी स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपरा और पहचान के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने समाज को आश्वस्त किया कि उनकी सुरक्षा, सम्मान और विकास के लिए सरकार हर स्तर पर कार्य करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम से पूर्व नानकमत्ता गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेककर प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं शांति की कामना की। कार्यक्रम में विधायक रूद्रपुर श्री शिव अरोरा,जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अजय मौर्य, मेयर श्री विकास शर्मा, कार्यक्रम के संयोजक पूर्व विधायक श्री प्रेम सिंह राणा,दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कार्मिकों को पत्र लिखकर दी शुभकामनाएं

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते चार साल में सरकारी सेवा में चयनित हुए कार्मिकों को डिजिटल माध्यम से पत्र लिखकर, उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकानाएं प्रेषित की है। मुख्यमंत्री धामी ने पत्र में कहा है कि उत्तराखण्ड की जनता द्वारा उन्हें वर्ष 2022 में दूसरी बार मुख्य मुख्य सेवक का दायित्व सौंपा गया था। इस जनादेश की भावना के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिन से ही प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए, सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती का व्यापक अभियान शुरु किया गया। इसके बाद बीते चार साल में राज्य सरकार द्वारा लगभग 30 हजार से अधिक युवाओं को राजकीय सेवक के रूप में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है, यह अभियान आगे भी जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्र में कहा है कि अब युवा अपनी शानदार प्रतिभा और कठोर मेहनत के आधार पर राजकीय सेवा में चयनित हो रहे हैं। इस योग्यतम चयन में जहाँ एक ओर युवाओं

की मेहनत और प्रतिभा का योगदान है, वहीं राज्य सरकार के कठोर नकल विरोधी कानून के साथ ही निष्पक्ष, ईमानदार और पारदर्शी चयन प्रक्रिया ने भी युवा प्रतिभा को उचित सम्मान मिलना सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय सेवक के रूप में चयन होना सभी कार्मिकों के परिवार के साथ ही राज्य सरकार के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होंने चयनित कार्मिकों से निष्पक्ष एवं ईमानदार रहकर अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन करने की अपील करते हुए कहा है कि राजकीय सेवक के रूप में वो मानवीय मूल्यों के साथ आमजन की सेवा में हमेशा तत्पर रहें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई चयनित युवाओं से दूरभाष पर बात कर उन्हें उत्साह पूर्वक जनसेवा में योगदान देने की भी अपील की है।

मुख्यमंत्री ने किया अत्याधुनिक एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से एचडीएफसी बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के अंतर्गत जनहित के लिए प्रदान की गई 4 अत्याधुनिक एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया। यह पहल राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। निजी संस्थाओं द्वारा जनहित में किया जा रहा सहयोग सामाजिक उत्तरदायित्व का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में समय पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। एचडीएफसी बैंक द्वारा बैं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई ये एम्बुलेंस जरूरतमंद लोगों तक त्वरित चिकित्सा सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। राज्य सरकार जनभागीदारी एवं संस्थागत सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने एचडीएफसी बैंक की इस जनकल्याणकारी पहल की सराहना करते हुए कहा कि बड़े धार्मिक आयोजनों, आपदा की स्थितियों तथा दूरस्थ क्षेत्रों में ऐसी सेवाएं अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य के अन्य पर्वतीय जनपदों और आगामी हरिद्वार कुंभ के लिए भी एचडीएफसी बैंक से बैं के माध्यम से और एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की अपेक्षा की है।

सम्पादकीय

उत्तराखण्ड सरकार का सराहनीय प्रयास नो व्हीकल डे

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत करने और कम से कम एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील पर उत्तराखण्ड सरकार ने फैसला लेते हुए सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे का प्रावधान किया है। इस फैसले को कारगार साबित करने के लिए कई अधिकारी और नेता सामने आकर सकारात्मक संदेश देते नजर आये। बीते शनिवार को साइकिल, पैदल और सार्वजनिक वाहनों में सफर करते हुए सरकार के प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। मंत्री भरत सिंह चौधरी और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने बस से यात्रा की। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी साइकिल चलाकर कार्यालय पहुंचे, अपर निदेशक सूचना आशीष त्रिपाठी और संयुक्त निदेशक सूचना केएस चौहान कई किलोमीटर पैदल चलकर ऑफिस गये तो संयुक्त निदेशक सूचना नितिन उपाध्याय ऑटो रिक्शा से अपने कार्यालय पहुंचे। ये प्रयास पेट्रोल-डीजल को बचाने का ही नहीं बल्कि प्राकृतिक संरक्षण और ट्रेफिक के बढ़ते बोझ को कम करने का भी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील दूरदर्शी तौर पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हालात को स्थिर रखने की दिशा में थी और हम देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि हम इस दिशा में गंभीरता दिखायें।

दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था लंबे समय से आयात पर निर्भर रही है, विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों और सोने के मामले में। हम अपनी आवश्यकता का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करते हैं। इसी प्रकार भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में भी शामिल है। इन दोनों वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भरता भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव डालती है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तब भारत में महंगाई का स्तर भी बढ़ जाता है। परिवहन महंगा होता है, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ते हैं और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है।

हालांकि हालात इतने चिंताजनक नहीं है। फरवरी 2026 में हमारी विदेशी मुद्रा का भण्डार करीब 725 अरब डॉलर के साथ अपने उच्चतम स्तर पर था अब मई 2026 में इसमें गिरावट ही आयी है अब ये भण्डार करीब 690 अरब डॉलर के आस-पास है। इस गिरावट को तुलनात्मक तौर पर देखा जाये तो इतनी चिंताजनक नही है। हालांकि कच्चे तेल की रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी ने जरूर प्रभावित किया है। इससे ईंधन और मंहगाई पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। मार्च में थोक मंहगाई दर करीब 3. 88 प्रतिशत के करीब थी जो अप्रैल में 8 प्रतिशत से अधिक आंकी गई है। रुपया रिकॉर्ड 5 फीसदी से ज्यादा टूट गया है और अपने एतिहासिक निचले स्तर पर है।

भारत सरकार ने फिलहाल आम भारतीय नागरिकों को राहत देने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास किया है। ऐसे में हमें भी जागरूक और जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। विकसित राष्ट्र वही बन सकते हैं जहां नागरिक राष्ट्रीय संसाधनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। जापान और यूरोपीय देशों में ऊर्जा संरक्षण केवल सरकारी नीति नहीं बल्कि सामाजिक संस्कृति का हिस्सा भी है। भारत को भी यदि विकसित राष्ट्र बनना है, तो उसे उपभोग की मानसिकता से बाहर निकलकर आवश्यक उपयोग की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

यदि हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पादों के दोहन की बात करें तो देश के लगभग सभी शहर धुंए और प्रदुषण के ढेर बनते जा रहे हैं। सड़कें सिकुड़ रही हैं और गाड़ियां किसी साहुकार के ब्याज की तरह दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। सिर्फ एक कार नहीं, दो या तीन कार रखना एक मिडिल क्लास परिवार का ट्रेंड बन गया है। अब आवश्यकता है कि हम इस अंधाधुंध दिखावे की दुनिया से निकलकर जरूरतों और देश की आर्थिक दिशा को समझने का प्रयास करे। हम समझे कि पेट्रोल और डीजल की बचत सिर्फ आर्थिक चेतावनी ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी हो सकता है। भारत आज इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार यदि ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों को थोड़ा और आसान कर दे तो हालात कहीं बेहतर हो सकते हैं।

वहीं सोने की बात की जाये तो भारतीय शादियों में आज भी सोना विशेष भूमिका निभाता है। देश में सोना केवल आभूषण नहीं बल्कि सुरक्षा और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। सदियों से भारतीय परिवार आर्थिक असुरक्षा के समय सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानते आए हैं। हालांकि अत्यधिक सोना आयात करने से देश का व्यापार घाटा बढ़ता है। विदेशी मुद्रा का बड़ा हिस्सा सोना खरीदने में खर्च हो जाता है, जबकि यह धन उद्योग, तकनीक, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास में लगाया जा सकता है। इसके लिए सरकार को आधुनिक निवेश के विकल्पों को मजबूत करना होगा और पूर्णत: विश्वास योग्य बनाना होगा।

जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को जिला योजना में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त

संवाददाता

चमोली। जनपद चमोली के समग्र एवं संतुलित विकास को गति देने के उद्देश्य से माननीय मंत्री, ग्राम्य विकास, लघु एवं

सूक्ष्म मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा जनपद के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना की बैठक आयोजित की गई।बैठक से पूर्व जिलाधिकारी गौरव कुमार ने मा. प्रभारी मंत्री जी को पुष्पगुच्छ देकर और शॉल भेटकर उनका स्वागत किया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक जिला योजना के अंतर्गत कुल 74 करोड़ 23 लाख 70 हजार रुपये के परिव्यय /योजनाओं को अनुमोदित किया गया। प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को जिला योजना में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले वर्ष जनपद में अनेक विकासपरक एवं जनहितकारी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं तथा आगामी वर्ष की योजना भी जनपद के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

बैठक के दौरान विभागवार लोक निर्माण विभाग, पेयजल, कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सिंचाई, उरेड़ा, पर्यटन, खेल एवं युवा कल्याण, स्वास्थ्य, उद्योग, पंचायती राज, शिक्षा एवं बाल विकास विभाग की प्रस्तावित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।

प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि योजनाओं को क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाए तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर समन्वय से अधिकतम लाभ आमजन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने अधूरे एवं गतिमान कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए चौन लिंक फेंसिंग (घेरबाड़) को प्राथमिकता देने को कहा। उद्यान विभाग को निर्देशित किया गया कि जनपद में कीवी उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए बड़े क्लस्टर विकसित किए जाएं तथा उत्पादन, मार्केटिंग एवं पैकेजिंग व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिल सके।

कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने कृषि विभाग को किसानों को अच्छी क्वालिटी के कृषि उपकरण सब्सिडी पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही फसलों को जंगली जानवरों

प्रभारी मंत्री ने पशुपालन विभाग को पहाड़ों की अर्थव्यवस्था के लिए "गेम चेंजर" बताते हुए जिला योजना के माध्यम से बड़े एवं प्रभावी कार्य किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पशुपालन से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। साथ ही अच्छी नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने मत्स्य पालन, डेयरी एवं सहकारिता जैसे क्षेत्रों को भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इन क्षेत्रों में अधिक कार्य करने पर जोर दिया। इस वर्ष जिला योजना में कृषि, उद्यान, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन जैसे आजीविका आधारित क्षेत्रों में विशेष रूप से नवाचार और उत्पादन परक कार्य रखे हैं , जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।जिला योजना को भौतिक, सामाजिक, आजीविका एवं अन्य चार प्रमुख क्षेत्रों में संतुलित रूप से विभाजित किया गया है। योजना में सड़क, पेयजल, सिंचाई एवं ऊर्जा जैसी आधारभूत सुविधाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल एवं युवा कल्याण जैसे सामाजिक क्षेत्रों को भी पर्याप्त प्राथमिकता दी गई है। वहीं स्वरोजगार एवं आजीविका संवर्धन आधारित योजनाओं को विशेष फोकस में रखा गया है।

जिला योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को सड़क एवं पुल निर्माण हेतु 6 करोड़ 25 लाख रुपये, राजकीय सिंचाई को 5 करोड़ 80 लाख रुपये, लघु सिंचाई को 2 करोड़ 80 लाख रुपये, पेयजल संस्थान को 5 करोड़ 20 लाख रुपये तथा पेयजल निगम को 2 करोड़ 40 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार पर्यटन विभाग को 5 करोड़ 10 लाख रुपये, प्रादेशिक विकास दल को 4 करोड़ 70 लाख रुपये, पशुपालन विभाग को 3 करोड़ 65 लाख रुपये, कृषि विभाग को 4 करोड़ 80 लाख रुपये तथा उद्यान विभाग को 5 करोड़ 5 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा हेतु 4 करोड़ 30 लाख रुपये तथा माध्यमिक शिक्षा हेतु 4 करोड़ 25 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। वन विभाग को 1 करोड़ रुपये तथा उरेड़ा को 1 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। चिकित्सा विभाग में एलोपैथिक चिकित्सा के लिए 2 करोड़ 88 लाख रुपये, आयुर्वेद विभाग हेतु 70 लाख रुपये तथा होम्योपैथिक विभाग हेतु 11 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया। वहीं सहकारिता विभाग को 60 लाख रुपये तथा मत्स्य विभाग को 85 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई।जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी विनय जोशी ने बताया कि इस वर्ष की जिला योजना में 51.91 प्रतिशत धनराशि नए कार्यों के लिए, 31. 22 प्रतिशत धनराशि वचनबद्ध एवं मानदेय मद में तथा 16.87 प्रतिशत धनराशि स्वरोजगार योजनाओं हेतु निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि जनपद की देनदारियां अपेक्षाकृत कम रही हैं तथा भविष्य में भी देनदारियां न्यूनतम रखने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। बैठक में कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक भूपाल राम टम्टा,राज्य मंत्री हरक सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट, भाजपा जिला अध्यक्ष गजपाल बर्त्वाल,नगर पालिका अध्यक्ष संदीप रावत, डीएफओ सर्वेश दुबे,पीडी आनंद सिंह, डीडीओ के के पंत सहित जनप्रतिनिधि एवं सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

वनचेतना केन्द्र में हुआ वनाग्नि नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन

संवाददाता

बड़कोट /उत्तरकाशी। शनिवार को अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट के अंतर्गत वनचेतना केन्द्र बड़कोट में वनाग्नि नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन उप प्रभागीय वन अधिकारी साधुलाल पलियाल के अध्यक्षता में किया गया। जिसमें एन. डी आर एफ., एस. डी. आर. एफ. व वन विभाग के कर्मियों ने संयुक्त रूप से प्रतिभाग कर वनाग्नि नियंत्रण एवं प्रबन्धन हेतु जानकारियां साझा की।

उक्त कार्यक्रम में उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वनाग्नि नियंत्रण व प्रबंधन हेतु किए जा रहे विभागीय कार्यों को विस्तृत रूप में जानकारी दी गई तथा एन.डी. आर.एफ. इंचार्ज इंस्पेक्टर मंजीत सिंह द्वारा भी वनकर्मियों से वनाग्नि नियंत्रण में ग्राउंड स्तर पर आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी ली तथा वनाग्नि नियंत्रण हेतु विभिन्न उपकरणों व मास्टर कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर उनके कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी ली गयी और वनाग्नि नियंत्रण हेतु वन विभाग का सहयोग देने के लिए आश्वस्त किया!उक्त कार्यक्रम में वनक्षेत्राधिकारी रवाई शेखर सिंह राणा, वन क्षेत्राधिकारी मुंगरसन्ती विवेक चौहान ,वनक्षेत्राधिकारी सचिन एवं अन्य वनकर्मी उपस्थित रहे।

पूर्व मुख्यमंत्री खंडूड़ी की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी (से.नि) को हरिद्वार स्थित खड़खड़ी श्मशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी (से.नि) की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा और हर वर्ग के लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार के दौरान सेना एवं पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें अंतिम सलामी दी। उनके पुत्र श्री मनीष खंडूरी ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की।

इस दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी का निधन राज्य और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने सेना, केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री के रूप में पारदर्शिता और अनुशासन के साथ उत्कृष्ट कार्य किए। उन्होंने कहा कि वह हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उनकी कमी एक अभिभावक के रूप में हमेशा महसूस होगी। केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी का जीवन सादगी, अनुशासन और ईमानदारी का उदाहरण रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सेना अधिकारी के रूप में हर दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाया। उनके कार्यों को उत्तराखंड ही नहीं, पूरा देश हमेशा याद रखेगा। सुशासन और लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण विचारों को आगे बढ़ाने में उनका योगदान प्रेरणादायक रहा। इस अवसर पर पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र/पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, श्री तीरथ सिंह रावत, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा, महामंत्री संगठन श्री अजेय कुमार, सांसद श्री अनिल बलूनी, श्री अजय भट्ट , कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, श्री सतपाल महाराज, डॉ .धन सिंह रावत, श्री गणेश जोशी, श्री सौरभ बहुगुणा, श्री मदन कौशिक, श्री प्रदीप बत्रा, श्री खजान दास, विधायकगण, संतगण मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने पार्थिव शरीर को कंधा देकर अंतिम विदाई दी

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को बलवीर रोड, देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी (सेवानिवृत्त) के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नम आंखों से विदाई दी। मुख्यमंत्री ने पार्थिव शरीर को कंधा देकर अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी का संपूर्ण जीवन अनुशासन, सादगी, ईमानदारी और राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने उत्तराखंड के विकास एवं जनसेवा में जो योगदान दिया, उसे यह प्रदेश सदैव याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूरणीय क्षति बताया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी भूषण, महामंत्री (संगठन) श्री अजेय कुमार, कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत, श्री खजान दास, पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत, मेयर श्री सौरभ थपलियाल, महानगर अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

उपराष्ट्रपति ने अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि

देहरादून। उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूरी जी को आज देहरादून स्थित उनके आवास पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मेजर जनरल खंडूरी को एक असाधारण नेता, एक उत्कृष्ट सैनिक और एक अनुभवी प्रशासक के रूप में स्मरण किया जाएगा, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र और उसके लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि संपर्क में सुधार और भारत के सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में मेजर जनरल खंडूरी का योगदान देश के विकास पथ में एक अमिट विरासत बना रहेगा।

विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भूषण ने पिता के नाम लिखा संदेश

देहरादून। उत्तराखंड में दो बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी का आज निधन हो गया। उनकी बेटी विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भूषण ने पिता के नाम संदेश लिखा। उन्होंने लिखा मैंने केवल अपने पिता को नहीं खोया, बल्कि अपने जीवन के सबसे बड़े संबल, मार्गदर्शक और उस व्यक्तित्व को विदा किया है जिसकी छाया में मैंने कर्तव्य, अनुशासन और सेवा का अर्थ समझा।

मेजर जनरल (रि.) भुवन चंद्र खण्डूरी जी का जीवन किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति सम्पूर्ण समर्पण की एक जीवंत गाथा था। 1 अक्टूबर 1934 को प्रारम्भ हुई उनकी जीवन यात्रा भारतीय सेना के रणक्षेत्रों से लेकर लोकतंत्र के सर्वोच्च मंचों और उत्तराखंड की जनसेवा तक पहुँची, लेकिन हर भूमिका में उनकी पहचान एक ही रहीख़राष्ट्र प्रथम।

1954 में भारतीय सेना की कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन प्राप्त करने के साथ उन्होंने मातृभूमि की सेवा का जो संकल्प लिया, उसे जीवन भर निभाया। उन्होंने 1962 के भारतख़चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारतख़पाक युद्धों में देश के लिए अपना कर्तव्य निभाया। सीमाओं पर बिताए वे वर्ष केवल एक सैनिक के साहस की कहानी नहीं थे, बल्कि उन अनगिनत त्यागों की भी कहानी थे जो एक सैनिक का परिवार मौन रहकर करता है।

जब वे सीमा पर राष्ट्र की सुरक्षा में तैनात रहते थे, तब परिवार ने भी उनके साथ एक अलग युद्ध जियाख़प्रतीक्षा का, अनिश्चितता का और मौन चिंता का। हमारे बचपन के अनेक क्षण ऐसे रहे जब पिता का स्नेह पत्रों में मिलता था, उनकी उपस्थिति स्मृतियों और प्रतीक्षा में महसूस होती थी। लेकिन उन्होंने हमें कभी शिकायत नहीं, बल्कि गर्व करना सिखायाख़कि राष्ट्रसेवा केवल सैनिक नहीं करता, उसका परिवार भी उस संकल्प का सहभागी होता है।

सेना में लगभग छत्तीस वर्षों की गौरवपूर्ण सेवा के दौरान उन्होंने नेतृत्व, साहस और कर्तव्यनिष्ठा की ऐसी मिसाल स्थापित की कि 26 जनवरी 1982 को उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल (टैड) से सम्मानित किया गया। मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्होंने विश्राम का मार्ग नहीं चुना। 1991 में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर उन्होंने जनसेवा को अपना नया दायित्व बनाया।

गढ़वाल की जनता ने उन्हें बार-बार संसद भेजा और उन्होंने सांसद, केंद्रीय मंत्री तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की। भारत सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री रहते हुए उन्होंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसी ऐतिहासिक योजनाओं को गति दी, जिसने आधुनिक भारत की विकास यात्रा को नई दिशा दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सादगी, पारदर्शिता और सुशासन का पर्याय बना। मजबूत लोकायुक्त कानून, प्रशासनिक सुधार और जनहित को सर्वोच्च रखने का उनका आग्रह सदैव याद रखा जाएगा।

लेकिन मेरे लिए उनकी सबसे बड़ी पहचान किसी पद या सम्मान से नहीं थी।

वे मेरे पिता थेख़कम बोलने वाले, लेकिन मूल्यों पर अडिग; कठोर दिखने वाले, लेकिन भीतर से अत्यंत संवेदनशील। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में ईमानदारी सबसे बड़ी पूँजी है, और पद की गरिमा व्यक्ति के आचरण से बनती है। उनसे मैंने सीखा कि सार्वजनिक जीवन में निर्णय लोकप्रिय होने के लिए नहीं, सही होने के लिए लिए जाते हैं।

आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो समझ पाती हूँ कि राष्ट्र ने जिन उपलब्धियों और सेवाओं के लिए उन्हें सम्मान दिया, उनके पीछे एक ऐसा जीवन था जिसने व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं से अधिक कर्तव्य को चुना। परिवार ने भी उनका समय, उनकी उपस्थिति और जीवन के अनेक निजी क्षण राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित होते देखे, और यही त्याग हमारे लिए गर्व का आधार बना।

वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच खुले द्वितीय केदार श्री मद्महेश्वर धाम के कपाट

रुद्रप्रयाग। पंच केदारों में द्वितीय केदार के रूप में विख्यात भगवान श्री मद्महेश्वर जी मंदिर के कपाट आज श्रद्धा, आस्था एवं सनातन परंपराओं के मध्य विधि-विधान के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। कपाटोद्घाटन के पावन अवसर पर पूरा ध ाम "हर-हर महादेव" और भगवान मद्महेश्वर के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। भगवान मद्महेश्वर की उत्सव डोली कल रात्रि विश्राम गोण्डार में करने के उपरांत आज प्रात: गोण्डार गाँव से पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों एवं भक्तिमय वातावरण के बीच धाम के लिए रवाना हुई। डोली यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह एवं भक्ति देखने को मिली। प्रात: लगभग 10:45 बजे उत्सव डोली मद्महेश्वर धाम पहुंची, जहां मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण, विशेष पूजा-अर्चना एवं धार्मिक अनुष्ठानों के साथ कपाट खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। मुख्य पुजारी श्री शिव शंकर लिंग सहित वेदपाठियों द्वारा पूजा संपन्न होने के पश्चात लगभग 11 बजे जैसे ही मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए, पूरा धाम शिवमय वातावरण में डूब गया। इस दौरान उपस्थित लगभग 1135 श्रद्धालुओं ने भगवान मद्महेश्वर के प्रथम दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया तथा देश एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और कल्याण की कामना की। कपाटोद्घाटन अवसर पर मंदिर समिति एवं प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा, आवागमन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखा गया। यात्रा मार्ग पर भी श्रद्धालुओं की सुविध ा हेतु व्यापक प्रबंध किए गए थे। हिमालय की गोद में स्थित श्री मद्महेश्वर धाम अपनी दिव्यता, आध्यात्मिक आभा एवं प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विशेष पहचान रखता है। कपाट खुलने के साथ ही अब यहां देश-विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। कपाटोद्घाटन के दौरान मंदिर समिति सदस्य प्रहलाद पुष्पवान, डोली प्रभारी किशन त्रिवेदी, प्रधान गोंडार अनूप पंवार,पूर्व प्रधान भगत सिंह पंवार, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य शिवानंद पंवार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में मुख्यमंत्री के निर्देशों के मिल रहे हैं सकारात्मक परिणाम

सूचना विभाग में 70 किलोवाट सोलर प्लांट से बिजली बिल में भारी कमी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव दिख रहे हैं। देहरादून स्थित उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अपने रिंग रोड, 6 नंबर पुलिया, रायपुर स्थित मुख्यालय में 70 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है। इस पहल का सकारात्मक प्रभाव पहले ही महीने में दिखाई दिया, जब अप्रैल 2026 में विभाग का बिजली बिल घटकर मात्र 1700 रह गया। पूर्व में विभाग को कमर्शियल टैरिफ के तहत प्रतिमाह लगभग 1 लाख 20 हजार बिजली बिल के रूप में भुगतान करना पड़ता था। यह सोलर पावर प्लांट उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण (उरेडा) द्वारा विशेष व्यवस्था के तहत विभाग में नि:शुल्क स्थापित किया गया है। उत्पादित बिजली को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से जोड़ा गया है, जिससे निर्बाध एवं स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में यह पहल ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग बंशीधर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने एवं सरकारी विभागों में इसके अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री सौर स्वरोजगार योजना राज्य में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले चार वर्षों में उत्तराखंड में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन 1000 मेगावाट की सीमा को पार कर चुका है। सूचना विभाग के निदेशालय में स्थापित 70 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट इसी दिशा में एक प्रभावी पहल है। श्री तिवारी ने बताया कि एमडीडीए द्वारा आईएसबीटी परिसर में 100 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है तथा अन्य कार्यालयों में भी इस दिशा में कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त सिटी फॉरेस्ट पार्क में पंप एवं स्ट्रीट लाइट्स का संचालन भी सोलर ऊर्जा के माध्यम से किया जा रहा है।उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित कर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में सहभागी बनें।

पर्यटन पर सरकार का फोकस

बदले-बदले नजर आयेंगे केदारघाटी और जोशीमठ

देहरादून: केदारघाटी और जोशीमठ को संवारने और पर्यटन की नजर से विकसित करने के लिए सरकार ने कदम बढ़ा दिये हैं। सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में दो अहम परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठकों में रुद्रप्रयाग जनपद के रतूड़ा गांव में प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह तथा चमोली जिले के जोशीमठ के रविग्राम में प्रस्तावित मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने और आवश्यक सुधारों के साथ संशोधित प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

रतूड़ा में बनेगा आधुनिक पहाड़ी शैली का राज्य अतिथि गृह

बैठक में रुद्रप्रयाग जनपद के ग्राम रतूड़ा में प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर विचार-विमर्श किया गया। करीब 34.29 करोड़ रुपये लागत वाली इस परियोजना को मुख्यमंत्री घोषणा से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य बताया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान सचिव राज्य संपत्ति डॉ. राजेश कुमार ने कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भवन का डिजाइन पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए ताकि स्थानीय संस्कृति और आधुनिक सुविधाओं का बेहतर समन्वय दिखाई दे। उन्होंने कहा कि अतिथि गृह में 20 आधुनिक कक्षों के साथ दो वीवीआईपी सुइट और आवश्यक घरेलू सुविधाओं का समुचित प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा परियोजना को अधिक उपयोगी और आकर्षक बनाने के लिए जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक संशोधन किए जाएं। बैठक में विद्युत कार्यों की अलग डीपीआर तत्काल प्रस्तुत करने तथा सभी आवश्यक सुविधाओं को शामिल करते हुए संशोधित आगणन शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

केदारनाथ यात्रा क्षेत्र को मिलेगा नया लाभ

रतूड़ा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त राज्य अतिथि गृह बनने से केदारनाथ यात्रा मार्ग और आसपास के पर्यटन क्षेत्रों में आने वाले विशिष्ट अतिथियों, अधिकारियों तथा पर्यटकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। राज्य सरकार इस परियोजना को पर्यटन अवसंरचना के विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण मान रही है।

जोशीमठ में पार्किंग संकट दूर करने की तैयारी

दूसरी बैठक में चमोली जिले के जोशीमठ स्थित रविग्राम में प्रस्तावित मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना की समीक्षा की गई। औली देश-विदेश के पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण केंद्र है और वर्षभर बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण जोशीमठ और औली क्षेत्र में यातायात दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए लगभग 5.69 करोड़ रुपये लागत से मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बैठक में बताया गया कि परियोजना के तहत लोअर ग्राउंड स्तर पर 51 तथा ग्राउंड फ्लोर पर 46 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 97 कारों के लिए पार्किंग सुविधा विकसित की जाएगी। पार्किंग परिसर तक पहुंचने के लिए सात मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित किया गया है। चयनित भूमि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है तथा उसे जिला विकास प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जारी है।

सुरक्षा और सुगमता पर विशेष जोर

परियोजना पर विस्तृत चर्चा के बाद सचिव आवास विभाग डॉ. राजेश कुमार ने पार्किंग परिसर तक पहुंचने वाले मार्ग को और अधिक सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मार्ग की चौड़ाई एक से दो मीटर तक बढ़ाने और प्रवेश तथा निकास मार्गों को अलग-अलग करने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था विकसित करने को कहा। इससे यातायात संचालन अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित हो सकेगा। साथ ही जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि चयनित भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया एक माह के भीतर पूरी कर शासन को अवगत कराया जाए।

पर्यटन और विकास को मिलेगी नई गति

सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं को उत्तराखंड में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक आधारभूत ढांचे के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। एक ओर रुद्रप्रयाग में अत्याधुनिक राज्य अतिथि गृह के निर्माण से केदारघाटी में सरकारी एवं पर्यटन सुविधाओं को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर जोशीमठ में मल्टीलेवल पार्किंग बनने से औली आने वाले पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुरूप शासन इन परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है, ताकि पर्यटन, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिल सके।

माधुरी की किस्मत में ही सुपरस्टार बनना लिखा था

नई दिल्ली। माधुरी की किस्मत में ही सुपरस्टार बनना लिखा था। इसिलिए तो ऊपर वाले ने माधुरी को इस आदमी से मिलाया था। ये हैं रिक्कू राकेशनाथ। पहली दफा रिक्कू राकेशनाथ और माधुरी दीक्षित की मुलाकात तब हुई थी जब माधुरी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। माधुरी उन दिनों पेइंग गेस्ट नामक एक टीवी शो में काम कर रही थी।

उस शो की शूटिंग चांदीवली स्टूडियो में चल रही थी। वहीं पर रिक्कू राकेशनाथ और माधुरी पहली दफा मिले थे। रिक्कू राकेशनाथ को माधुरी से मिलवाया था खातून नामक एक महिला ने। वो महिला उन दिनों माधुरी की हेयरड्रैसर थी। रिक्कू राकेशनाथ से खातून की जानकारी सलमा आगा के जरिए हुई थी।

सलमा आगा भी किसी वक्त पर रिक्कू राकेशनाथ की क्लाइंट थी। तब खघतून नाम की वो महिला सलमा आगा की हेयरड्रैसर हुआ करती थी। खातून ने रिक्कू राकेशनाथ को बताया कि माधुरी बहुत टैलेंटेड लड़की है। उसका चेहरा भी बहुत अच्छा है। जब रिक्कू राकेशनाथ खुद माधुरी से मिले तो उन्हें अहसास हुआ कि खातून ने माधुरी के बारे में जो कहा था, सही कहा था।

शुरुआती हाय-हैलो और थोड़ी सी बातचीत के बाद माधुरी पेइंग गेस्ट के अपने एक सीन की शूटिंग में व्यस्त हो गई। रिक्कू राकेशनाथ एक कोने में खड़े होकर माधुरी को परफॉर्म करते देखने लगे। माधुरी जिस आत्मविश्वास के साथ एक्टिंग कर रही थी, उससे रिक्कू राकेशनाथ बहुत प्रभावित हो रहे थे। शूटिंग के बाद रिक्कू राकेशनाथ ने माधुरी से उनके घर का नंबर ले लिया।

एक दिन रिक्कू राकेशनाथ ने माधुरी को फोन किया। माधुरी ने उन्हें घर आने को कहा। रिक्कू माधुरी के घर पहुंचे। वहां माधुरी की मां से भी उनकी मुलाकात हुई। और रिक्कू राकेशनाथ ने उनके साथ चाय वगैरह भी पी। एक इंटरव्यू में रिक्कू राकेशनाथ ने बताया था कि माधुरी के घर हुई उस पहली विजिट के बाद उन्हें पता चला कि वो लोग वैसे ही हैं जैसे कोई भी आम मराठी फैमिली होती है। यानि एकदम सिंपल।

इसी दौरान एक दिन खातून ने माधुरी को सुभाष घई से भी मिलवाया। सुभाष घई उन दिनों कर्मा फिल्म बना रहे थे। और एक छोटे से डांस सीक्वेंस के लिए उन्हें किसी ऐसी एक्ट्रेस की जरूरत थी जो डांस कर लेती हो। सुभाष घई ने वो रोल माधुरी को दे दिया। माधुरी ने वो डांस सीक्वेंस शूट भी किया था। लेकिन कर्मा की फाइनल एडिटिंग के दौरान सुभाष घई ने वो डांस सीक्वें हटा दिया। कहा जाता है कि सुभाष घई माधुरी के टैलेंट से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्हें कर्मा के उस छोटे से रोल से माधुरी को अपनी फिल्म में दिखाना सही नहीं लग रहा था। सुभाष घई माधुरी को लीड हीरोइन के तौर पर लॉन्च करना चाहते थे। जो बाद में उन्होंने किया भी। सुभाष घई ने माधुरी को अपनी फिल्म उत्तर-दक्षिण में हीरोइन लिया था। ये भी कहा जाता है कि सुभाष घई ने कई दूसरे डायरेक्टर्स-प्रोड्यूसर्स को भी माधुरी का नाम रिकमेंड किया था।

रिक्कू राकेशनाथ उन दिनों अनिल कपूर का काम भी संभाल रहे थे। तो

उन्होंने अनिल कपूर के भाई और प्रोड्यूसर बोनी कपूर से भी माधुरी दीक्षित के बारे में बात की। फिर एक दिन बोनी कपूर रिक्कू राकेशनाथ को अपने साथ सुभाष घई के ऑफिस लेकर गए। वहां इन लोगों ने इस बारे में चर्चा किया कि माधुरी को कैसे प्रमोट किया जाए।

तय हुआ कि स्क्रीन मैगजीन में माधुरी के नाम से एक विज्ञापन दिया जाएगा। विज्ञापन में लिखा जाएगा कि एफ.सी. मेहरा, यश चोपड़ा, शशि कपूर और अशोक ठकेरिया जैसे बड़े प्रोड्यूसर्स माधुरी के साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं। माधुरी एक उभरता हुआ सितारा है। कुछ ऐसा विज्ञापन इन लोगों ने स्क्रीन मैगजीन में पब्लिश करा दिया।

लेकिन सच ये था कि उस वक्त इनमें से कोई भी प्रोड्यूसर माधुरी के साथ कोई फिल्म नहीं बना रहा था। यानि वो विज्ञापन(जो कि एक पेड आर्टिकल था।) सिर्फ माधुरी की हाइप बनाने के लिए दिया गया था। साल 1984 में माधुरी की पहली फिल्म अबोध रिलीज हुई। अबोध रिलीज होने के पहले सप्ताह के बाद से ही रिक्कू राकेशनाथ ऑफिशियली माधुरी दीक्षित के सेक्रेटरी के तौर पर काम करने लगे।

अबोध बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इसलिए माधुरी व रिक्कू राकेशनाथ ने फैसला किया कि वो इस फिल्म को थिएटर में जाकर नहीं देखेंगे। दरअसल, रिक्कू राकेशनाथ अपने लिए इस फिल्म को नहीं देखना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं माधुरी का काम उन्हें पसंद ना आए और वो माधुरी के सेक्रेटरी के तौर पर काम करने को लेकर सोच में ना पड़ जाएं।

इस वक्त तक माधुरी कुछ और फिल्में खुद से साइन कर चुकी थी जैसे आवारा बाप, स्वाति, मोहरे इत्यादि। इन फिल्मों में माधुरी के रोल तो छोटे थे। लेकिन ये फिल्में बड़ी थी। उस वक्त माधुरी को सेकेंड या थर्ड लीड कैरेक्टर्स मिल रहे थे। अबोध के पिटने और सिनेमाघरों से उतर जाने के बाद रिक्कू राकेशनाथ ने इंडस्ट्री के टॉप फोटोग्राफर्स जैसे जे.पी.सिंघल, राकेश श्रेष्ण व जयेश सेठ इत्यादि से माधुरी दीक्षित का एक बढ़िया सा पोर्टफोलिया बनवाया। रिक्कू राकेशनाथ ने जो पहली सबसे सफल फिल्म माधुरी दीक्षित को दिलाई, वो थी तेजाब। माधुरी को तेजाब कैसे मिली थी, ये जानने लायक बात है। और बड़ी दिलचस्प बात भी है। फिल्मकार टी रामा राव ने माधुरी को अपनी फिल्म खतरों के खिलाड़ी में साइन किया। उस फिल्म में धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे व नीलम भी थे। उस वक्त फिल्म मैगजीन्स व अखबारों में जो विज्ञापन खतरों के खिलाड़ी फिल्म का दिया गया था, उसमें फिल्म की स्टारकास्ट में माधुरी का नाम सबसे नीचे लिखा गया था। ये बात रिक्कू राकेशनाथ को अच्छी नहीं लगी। रिक्कू राकेशनाथ ने इस बारे में टी रामा राव से बात की और कहा कि माधुरी को संजय दत्त के अपोजिट कास्ट किया गया है।

संजय दत्त फिल्म के सैकेंड लीड हैं। इसलिए माधुरी का नाम ऊपर लिखा जाना चाहिए। टी रामा राव ने रिक्कू जी से कहा कि स्टारकास्ट के नाम सीनियोरिटी के अनुसार दिए गए हैं। रिक्कू जी ने उनसे कहा कि माधुरी नीलम से सीनियर हैं। टी रामा राव थोड़ा कन्फ्यूज हुए। फिर उन्होंने रिक्कू राकेशनाथ से कहा कि साबित कीजिए माधुरी नीलम से सीनियर हैं।

तब रिक्कू राकेशनाथ पहुंचे रमेश बहल के पास। रमेश बहल की फिल्म जवानी से नीलम का डेब्यू हुआ था। रिक्कू जी ने रमेश बहल से एक ऐसा लैटर देने की विनती की जिसमें उनकी फिल्म जवानी की रिलीज डेट लिखी हो। रमेश बहल ने वो लैटर रिक्कू जी को दे दिया। उसके बाद रिक्कू पहुंचे राजश्री प्रोडक्शन्स के ऑफिस। माधुरी की डेब्यू फिल्म अबोध राजश्री ने ही बनाई थी।

राजश्री वालों ने भी उन्हें अबोध की लिखित रिलीज डेट वाला लैटर दे दिया। नीलम की जवानी और माधुरी की अबोध , दोनों ही 1984 में रिलीज हुई थी। लेकिन अबोध, जवानी से पहले रिलीज हुई थी। इस तरह रिक्कू राकेशनाथ ने टी रामा राव को साबित करके दिखाया कि माधुरी नीलम से सीनियर हैं। टी रामा राव को माधुरी का नाम नीलम से ऊपर करना पड़ा।

जब रिक्कू राकेशनाथ अबोध की रिलीज डेट का लिखित लैटर लेने के लिए राजश्री प्रोडक्शन्स के ऑफिस गए थे, तब वहां उनकी मुलाकात चंद्रशेखर नरवेकर से हुई। चंद्रशेखर नरवेकर रिक्कू जी के पुराने दोस्त थे। और जानते हैं ये चंद्रशेखर नरवेकर कौन थे? ये थे मशहूर डायरेक्टर एन. चंद्रा। जी हां, एन. चंद्रा जी का रियल नेम चंद्रशेखर नरवेकर है।

रिक्कू राकेशनाथ और चंद्रशेखर नरवेकर उर्फ एन. चंद्रा की जान-पहचान तब से थी जब एन. चंद्रा गुलजार साहब के असिस्टेंट हुआ करते थे। राजश्री प्रोडक्शन्स के ऑफिस में उस दिन एन. चंद्रा ने रिक्कू से कहा,ष्तुम जानते हो, मैं तुम्हारे हीरो को साइन कर रहा हूं।ष एन. चंद्रा अनिल कपूर की बात कर रहे थे। और चूंकि रिक्कू जी तब अनिल कपूर का काम भी संभाल रहे थे तो उन्हें एन. चंद्रा के बताने से पहले ही इस बात की जानकारी थी। मगर जब एन. चंद्रा ने जिक्र किया कि वो अनिल के अपोजिट किसी नई लड़की को हीरोइन लेंगे, तो रिक्रू जी ने उन्हें फौरन माधुरी दीक्षित की तस्वीरें दिखाई। एन. चंद्रा तब तक भी माधुरी को नहीं पहचानते थे। इसलिए उन्होंने रिक्कू राकेशनाथ से पूछा कि क्या वो माधुरी का कोई काम या किसी सीन की कोई रश फुटेज देख सकते हैं? रिक्कू राकेशनाथ ने फौरन उनके लिए माधुरी की रश फुटेज का इंतजाम कर दिया। वो इंतजाम ऐसे हुआ कि माधुरी की डेब्यू फिल्म अबोध को राजश्री प्रोडक्शन्स ने ही बनाया था।

उस वक्त ये दोनों राजश्री के ऑफिस में ही बैठे थे। रिक्कू जी ने राजश्री के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की, कि एन. चंद्रा को अबोध फिल्म वाले माधुरी के कुछ दृश्य दिखाए जाएं। राजश्री वालों ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली। लंच ब्रेक के दौरान एन. चंद्रा के लिए अबोध की कुछ क्लिप्स प्ले की गई। अबोध में माधुरी ने एक पारंपरिक भारतीय लड़की का किरदार निभाया था।

एन. चंद्रा को माधुरी और उनका काम पसंद आया। अबोध में माधुरी ने डांस भी किया था। एन. चंद्रा सबसे अधिक प्रभावित माधुरी के डांस से ही हुए थे। आखिरकार एक दिन रिक्कू राकेशनाथ ने माधुरी और एन. चंद्रा को मिलवाया। कुछ बातचीत के बाद एन. चंद्रा ने माधुरी को तेजाब फिल्म की हीरोइन के तौर पर साइन कर लिया।

अनिल कपूर को बताया गया कि तेजाब में उनकी हीरोइन एक नई हीरोइन होगी। और ये नई हीरोइन वही है जिसने अबोध में काम किया था। अनिल कपूर ने कहा कि वो अच्छी दिखती है। लेकिन वो कैबरे डांसर तो बिल्कुल भी नहीं लगती। मगर बाद में अनिल कपूर को भी पता चल ही गया कि माधुरी क्या चीज हैं।

खैर, माधुरी का ऑडिशन लिया गया। माधुरी उस ऑडिशन में पास हो गई। माधुरी के ऑडिशन के वक्त बाबा आजमी कैमरा संभाल रहे थे। उन्हें भी माधुरी बहुत पसंद आई। माधुरी ने तेजाब में काम किया। तेजाब रिलीज हुई। और तेजाब ने उस साल बॉक्स ऑफिस पर क्या गदर मचाया था ये तो हम सभी जानते है। 1988 की सबसे कामयाब फिल्म साबित हुई थी तेजाब। माधुरी की किस्मत का सितारा तेजाब के रिलीज होने के बाद पूरी तरह से बदल गया था। फिल्म इंडस्ट्री में हर तरफ माधुरी-माधुरी हो रहा था। और माधुरी दीक्षित को वो सफलता दिलाने वाला शख्स कौन था? रिक्कू राकेशनाथ। सोचिए अगर खतरों के खिलाड़ी फिल्म के एक विज्ञापन में माधुरी का नाम ऊपर पब्लिश कराने के लिए उस दिन रिक्कू राकेशनाथ टी रामा राव से ना भिड़ते और तमाम भागदौड़ ना करते, तो क्या माधुरी को तेजाब फिल्म मिल पाती? नहीं। माधुरी की किस्मत में सुपरस्टार बनना लिखा था।

आजाद हिंद फौज का एक सिपाही जिसे अंग्रेजों ने फांसी की सजाई सुनाई

नई दिल्ली। आजाद हिंद फौज का एक सिपाही जिसे अंग्रेजों ने फांसी की सजाई सुनाई थी। एक वक्त था जब ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा हुआ करते थे। इन्होंने अंग्रेजों के लिए दूसरे विश्वयुद्ध भी लड़ा था। लेकिन बाद में अंग्रेजों से बगावत कर आजाद भारत का सपना लिए ये आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। अंग्रेजों ने इन्हें बागी करार दे दिया और पकड़ा तो मौत की सजा सुना दी। हालांकि इनके साथियों ने इन्हें बचा लिया। नाम है इनका नजीर हुसैन। और इन्हें भोजपुरी सिनेमा का पितामह भी कहा जाता है। तकरीबन 500 फिल्मों में काम करने वाले नजीर हुसैन अगर जिंदा होते तो आज 104 साल के हो चुके होते। जी हां, आज नजीर हुसैन जी का जन्मदिवस है। 15 मई 1922 को यूपी के गाजीपुर के एक गांव उसिया में नजीर हुसैन का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था शहबजाद खान। और वो रेलवे में गार्ड की नौकरी किया करते थे। नजीर हुसैन जब बड़े हुए तो पिता ने इन्हें भी रेलवे में ही फायरमैन की नौकरी दिला दी। हालांकि कुछ सालों बाद उस नौकरी से इनका मन उकता

गया। इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी जॉइन कर ली। दूसरा विश्वयुद्ध जब शुरू हुआ तो नजरी हुसैन की पोस्टिंग मलेशिया कर दी गई।

नक्सलमुक्त हो चुका है पूरा बस्तर : अमित शाह

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सहित इन सदस्य राज्यों और केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह बैठक केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत अंतर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की मेजबानी में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि यह बहुत हर्ष का विषय है कि यह बैठक बस्तर में आयोजित की जा रही है और इससे पहले ही आज पूरा बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि आज भारत के नक्सल मुक्त होने का संपूर्ण श्रेय हमारे सुरक्षाबलों के जवानों के परिश्रम और बहादुरी को जाता है। हमारी एजेंसियों ने बहुत सटीकता के साथ इनपुट एकत्र किए, सभी राज्यों के पुलिसबलों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के साथ मिलकर हर इनपुट पर सटीक कार्रवाई करने से संबंधित समयबद्ध निर्णय किए। इसके साथ ही Whole of the Government Approach के साथ सभी राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के सभी विभागों ने नक्सलमुक्त हुए क्षेत्रों में विकास को पहुंचाने का काम किया। श्री अमित शाह ने कहा कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र लगभग पांच दशक से विकास

की दौड़ में पिछड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इन क्षेत्रों को विकास के मामले में देश के बाकी क्षेत्रों के समकक्ष नहीं ले आते, तब तक हमारी लड़ाई समाप्त नहीं होगी। केन्द्रीय गृह मंत्री ने पूरे देश के नक्सल मुक्त होने के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन किया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में जो भी चीजें चाहिए थीं, उन्होंने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ समन्वय कर उन्हें प्राप्त किया और जहां नेतृत्व की जरूरत थी, वहां मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने नेतृत्व भी प्रदान किया और इसी का परिणाम है कि आज बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है। श्री अमित शाह ने कहा कि राज्यों के बीच के और राज्यों और केन्द्र के बीच के सभी विवादित मुद्दे समाप्त कर हम आज एक अच्छे वातावरण में यह बैठक कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि आज की बैठक में सभी एजेंडा विकास की मॉनिटरिंग से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संघीय ढांचा मजबूत हुआ है और क्षेत्रीय परिषद की बैठकें निरंतर हो रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप बहुत बड़े भूभाग में चार राज्यों के बीच और चार राज्यों का केन्द्र के साथ कोई विवाद ही नहीं बचा है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य हैं। उत्तर के हिमालय क्षेत्र से लेकर गंगा-यमुना के मैदानी भूभाग से लेकर मध्य भारत के पठारी, वन समृद्ध और खनिज समृद्ध क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं, जो निश्चित रूप से देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होने कहा कि यह क्षेत्र हमें देश के अनाज के भंडारों को भरने में बड़ी मदद करता है। इस क्षेत्र के समृद्ध खनिज भंडार से देश के विकास को गति मिलती है और इसी क्षेत्र की समृद्ध विरासत और संस्कृति ने देश को आगे बढ़ाने में मदद की है। इसी क्षेत्र में देश के आस्था के सभी केंद्र करीब-करीब एक ही जगह पर आए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लगभग सात राज्यों को जोड़ता है और इस दृष्टि से पूरे मध्य क्षेत्र का बहुत महत्व है। गृह मंत्री ने कहा कि आज यह पूरा क्षेत्र ना केवल नक्सल मुक्त हुआ है, बल्कि विवादों से भी मुक्त हुआ है, जो हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषद बैठकों का एक मजबूत और जीवंत तंत्र बना है - हमने इसे निर्णायक, निरंतर और परिणामदायी बनाया है। 2004 से 2014 के 10 वर्षों में क्षेत्रीय परिषद की मात्र 11 बैठकें हुई थीं, जो 2014 से 2026 के बीच बढ़कर 32 हो गई हैं। पहले 10 वर्षों में स्टैंडिंग कमेटी की 14 बैठकें हुई थीं, जो इस अवधि में ढाई गुना बढ़कर 35 हुई हैं। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 में मात्र 569 मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जबकि 2014 से 2026 में 1729 मुद्दों पर चर्चा हुई है, और उनमें से लगभग 80% मुद्दों का सफल निराकरण भी कर लिया गया है। लंबित मुद्दों में से अधिकांश मॉनिटरिंग से संबंधित हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का विवाद शेष नहीं है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन -2 पर हमें अभी से फोकस करना चाहिए और हर घर में नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, पोषण और समाज कल्याण बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों और सभी मुख्य सचिवों से आह्वान किया कि कुपोषण के खिलाफ भारत सरकार की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल ड्रॉपआउट दर और स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी और अधिक कार्य हों। वित्तीय समावेशन और बिजली सुधार इस विकसित क्षेत्र को पूर्ण विकसित बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि शहरी नियोजन, जन स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और बिजली सुधार के चारों क्षेत्र में भी और अधिक गति से कार्य करें। गृह मंत्री ने अपील की कि हमारा कम से कम 50% ध्यान ग्रामीण विकास और व्यक्ति को मजबूत बनाने वाली योजनाओं पर रहना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि हर 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक की सुविधा उपलब्ध होना बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारी सभी योजनाएं Direct Benefit Transfer (DBT) आधारित हैं, इसीलिए सभी राज्यों को इस दिशा में ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि POCSO और बलात्कार के मामलों में अगर समय से कछ। जांच हो जाए तो इनमें दोषसिद्धि की दर शत-प्रतिशत हो सकती है। श्री शाह ने कहा कि अदालतों में लंबित पड़े पाँच साल से अधिक पुराने मामलों के तेजी से निपटारे के लिए उच्च न्यायालयों को विशेष अदालतें गठित करनी चाहिए। गंभीर अपराधों में शासन को ऐसी गंभीरता दिखानी चाहिए। उन्होंने चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे 1930 हेल्पलाइन पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय के प्रारूप के अनुरूप ही राज्यों का प्रारूप लागू करें और राज्यों की हेल्पलाइन के कॉल सेंटर को अपडेट करें। श्री अमित शाह ने कहा कि मिलावटखोरी के मामलों में जो केस रजिस्टर्ड होता है और पेनल्टी लगती है तो उसकी प्रसिद्धि की भी व्यवस्था करनी चाहिए।

पूर्वी भारत बन सकता है देश के कृषि विकास का ग्रोथ इंजन : शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भुवनेश्वर के मेफेयर कन्वेंशन में ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी के साथ पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने पूर्वी भारत की कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, वैज्ञानिक और लाभकारी बनाने का सशक्त आह्वान किया। ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से जुड़े इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में दलहन-तिलहन उत्पादन, छोटी जोत वाले किसानों के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, किसान रजिस्ट्री, बागवानी, कृषि ऋण, विपणन, नकली कृषि आदानों पर नियंत्रण और किसान आय वृद्धि जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा का खाका रखा गया। पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह आयोजन केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूर्वी भारत की कृषि, किसानों की आजीविका और क्षेत्रीय कृषि रणनीति को नई दिशा देने के लिए गंभीर विचार-विमर्श का मंच है। श्री चौहान ने कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ की पावन धरती पर एकत्र हुई यह "टीम एग्रीकल्चर" पूर्वी भारत की खेती की हालत को बेहतर बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के संकल्प के साथ बैठी है। उन्होंने पूर्वी भारत की उर्वरा भूमि, जल उपलब्धता, विविध जलवायु और किसानों की मेहनत को इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि थोड़े से सही प्रयासों से यही क्षेत्र भारत के कृषि विकास का ग्रोथ इंजन बन सकता है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने किसानों को केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि जीवनदाता बताते हुए कहा कि किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध और शक्तिशाली भारत की ओर बढ़ रहा है और इस यात्रा की रीढ़ कृषि है। उन्होंने कृषि के सामने तीन प्रमुख लक्ष्य रखे- 140 करोड़ देशवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराना और किसानों की बेहतर आजीविका व आय वृद्धि सुनिश्चित करना। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना, नुकसान होने पर भरपाई करना और कृषि का विविधीकरण करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि केवल धान और गेहूं से काम नहीं चलेगा, बल्कि दलहन, तिलहन, फल, सब्जियां और अन्य उच्च मूल्य फसलों की ओर भी आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पूर्वी भारत में इन सभी क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वी राज्यों में छोटी जोत एक बड़ी वास्तविकता है, इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग को केवल नारा नहीं, बल्कि जमीन पर उतरा हुआ मॉडल बनाना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनाज के साथ फल, सब्जियां, मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन और कृषि वानिकी जैसी गतिविधियों को जोड़कर छोटे किसान की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने आईसीएआर, कृषि मंत्रियों और अधिकारियों से आग्रह किया कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल किसानों तक प्रेरक और व्यवहारिक रूप में पहुंचें। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने टिकाऊ कृषि की दिशा में मृदा स्वास्थ्य की रक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि संतुलित उर्वरक उपयोग पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि बिना मृदा परीक्षण के अंधाधुंध खाद का प्रयोग खर्च भी बढ़ाता है और धरती की सेहत भी बिगाड़ता है, इसलिए किसानों को आवश्यकतानुसार ही उर्वरक उपयोग के लिए प्रेरित करना होगा। उन्होंने प्राकृतिक खेती को भी प्रधानमंत्री के फोकस का क्षेत्र बताते हुए किसानों से अपनी जमीन के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह किया। श्री चौहान ने बताया कि 1 जून से "खेत बचाओ अभियान" शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से संतुलित खाद उपयोग, मिट्टी की सेहत, आधुनिक तकनीक, योजनाओं की जानकारी और किसान जागरूकता पर विशेष बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के डायवर्जन पर रोक लगानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि सब्सिडी वाला खाद केवल किसान और खेती के काम में ही उपयोग हो। उन्होंने नकली खाद, घटिया बीज और नकली कीटनाशकों को किसानों के खिलाफ बड़ा अपराध बताते हुए कहा कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कड़े कानून की आवश्यकता है और राज्यों को इस दिशा में सख्ती से कार्रवाई करनी होगी, ताकि किसानों की लागत न बढ़े और उन्हें गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान मिल सके। श्री शिवराज सिंह चौहान ने दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि पूर्वी क्षेत्र देश को इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की मजबूत क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि दाल और तिलहन की खेती को बढ़ावा तभी मिलेगा जब किसान को यह भरोसा होगा कि उसकी उपज की खरीद सुनिश्चित है, इसलिए पीएम-आशा, नैफेड, एनसीसीएफ और राज्य एजेंसियों की भूमिका को और प्रभावी बनाना होगा। केंद्रीय मंत्री चौहान ने वैज्ञानिक शोध और तकनीक को खेत तक पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि आईसीएआर, कृषि विज्ञान केंद्रों और वैज्ञानिक संस्थानों का ज्ञान सीधे किसानों तक पहुंचे, यह समय की मांग है।

स्वामी एवं प्रकाशक मौ. वसी के लिये मुद्रक नुसरत निशान खान द्वारा कौमी गुलदस्ता प्रिंटर्स, विलेज आमवाला, पोस्ट घंघौरा, देहरादून द्वारा, उत्तराखण्ड-248141 से मुद्रित एवं 5, लेन नम्बर 2, नामदेव एन्क्लेव फेस 2, ब्राहम्णवाला, देहरादून उत्तराखण्ड- 248171 से प्रकाशित। सम्पादक-मौ. वसी,
समस्त विवाद के लिये न्याय क्षेत्र देहरादून मान्य होगा। सम्पर्क- 9411112331
हमारे अखबार के ताजा अंक को ऑनलाइन पढ़ने के लिये www.aawamindia.com वेबसाइट पर जायें।
facebook: www.facebook.com/indiaaawam, youtube:www.youtube.com/@aawamindia,
X:www.x.com/aawamindia, Instagram:https://instagram.com/aawamindia